मध्य प्रदेश के जिलों मुख्य नगरों में स्वचालित इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की सुविधा

267. **श्री अजीत जोगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिला मुख्यालयों में और बड़े शहरों में स्वचालित इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन शहरों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री बिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं । इस समय कुल 45 जिला मुख्यालयों, जिनमें बड़े शहर भी शामिल हैं, में से 26 जिला मुख्यालयों में कम से कम एक आटोमेटिक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ख) आठवीं योजना के दौरान शेष स्थानों में उत्तरोत्तर आटोमेटिक एलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों ।

मध्य प्रदेश के गांवों में पत्रों के वितरण में अनियमितता

268. **श्री अजीत जोगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या बहुत अधिक है जहां पर चिट्ठियों का वितरण प्रतिदिन नहीं हो पाता ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले गांवों की संख्या कितनी है और यह सुविधा उन्हें कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री बिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) राज्य के सभी गांवों को दैनिक डाक का वितरण अनिर्धारित बीट सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है । इस प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई डाक-वस्तु का किसी गांव में वितरण करना हो तो उसके लिए वितरण एजेंट, द्वारा गांव में जाकर डाक वितरण कर दिया जाता है । तथापि यह संभव है कि किसी गांव विशेष में प्रतिदिन वितरण के लिए कोई डाक वस्तु न हो, तो ऐसी स्थिति में वितरण एजेंट उस गांव में नहीं जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, विभाग द्वारा नए डाकघर खोलने के लिए उन गांवों को प्राथमिकता दी जाती है जो मौजूदा निकटतम डाकघर से कि० मी० अथवा अधिक दूरी पर हों, ताकि वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके।

मध्य प्रदेश के इन्दौर और रायपुर शहरों में पब्लिक टेलीफोन बूथ

269. **श्री अजीत जोगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के इन्दौर और रायपुर शहरों में अब कितने पब्लिक टेलीफोन बूथ कार्यरत हैं ;

(ख) इनमें से विकलांगों को कितने पब्लिक टेलीफोन बूथ आवंटित किए गये हैं तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को ऐसे कितने बूथ आवंटित किए गए हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि विकलांगों को जो कमीशन इस समय दी जा रही है, वह बहुत कम है ; यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इसमें कुछ वृद्धि करने का विचार रखती है ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री बिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी नहीं ।